विकास 76 किमी लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 4415 करोड़ रुपये आएगी लागत

गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ेगा लिंक एक्सप्रेसवे

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। ग्रेटर नोएडा का जेवर एयरपोर्ट यूपी का ग्रोथ हब बनेगा। निर्यात को नई दिशा देने के लिए जेवर एयरपोर्ट से पूरे प्रदेश को जोड़ा जा रहा है। इसी के तहत जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। इसे यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए 24 किलोमीटर पहले से जोड़ा जाएगा। इसके निर्माण पर करीब 4415 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।

यह लिंक एक्सप्रेसवे 76 किलोमीटर लंबा होगा। इसके लिए यूपीडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इसका अंतिम बिंदु गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। वर्तमान में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ प्रदेश के बीच से गुजर रहे हैं। केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे उत्तर-दक्षिण में स्थित हैं। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के जरिये बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे कनेक्ट होगा।

पूरे प्रदेश से निर्यात और कार्गो का गढ़ बनेगा जेवर एयरपोर्ट

ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसी के साथ यूपी में एक्सप्रेसवे की पूरी ग्रिड अस्तित्व में आ जाएगी, जो यातायात को प्रदेश के किसी भी कोने में बाधा रहित सुविधा देगी।

एक्सपोर्ट हब और कार्गो हब से मिलेगी नई रफ्तार

जेवर एयरपोर्ट के नजदीक एक्सपोर्ट हब स्थापित किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयों को मिलेगा। विश्व बैंक की मदद से संचालित होने वाली यूपी एग्रीज योजना के तहत एसईजेड (स्पेशल इकोनामिक जोन) बनेगा। एक्सपोर्ट हब के जरिए मूंगफली, सब्जी, काला नमक चावल, तिल सहित कई उत्पादों के निर्यात में तेजी आएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र देश का सबसे बड़ा एयर कार्गो हब भी बनेगा। यूपी के उत्पाद तेजी से और प्रभावी तरीके से पूरी दुनिया तक पहुंचेंगे। बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के डिपो बनाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के पहले चरण में 37 एकड़ में कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है, जिसे भविष्य में 80 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। यह अब तक का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल होगा, जिसकी शुरुआती क्षमता प्रति वर्ष 2 लाख टन माल परिवहन की होगी। लिंक एक्सप्रेसवे इसकी क्षमता को और बढ़ाएगा।

प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे की सलाहकार कंपनी एडिकॉन इंडिया न्यूनतम बजट में अधिकतम लाभ वाले प्लान पर काम कर रही है। फरवरी में परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट नियोजन विभाग को भेज दी जाएगी। फिर मार्च तक इस परियोजना की लागत का अनुमोदन एम्पावर्ड फाइनेंस कमेटी से लिया जाएगा। मई से जुलाई के बीच में भूमि अधिग्रहण कर लिया जाएगा। अगले वर्ष फरवरी से निर्माण शुरु हो जाएगा। नए लिंक एक्सप्रेस की अनुमानित लागत 4415 करोड़ रुपये में से जमीन अधिग्रहण पर 4000 करोड़ खर्च होंगे।